

# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :- 2378/2016

अशोक कुमार

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये शिक्षा सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर—302005
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर—334001
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, श्रीगंगानगर—335001
4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, श्रीगंगानगर—335001
5. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, बीकानेर—334001

—प्रत्यर्थागण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 19.08.2016  
आदेश की दिनांक : 17.08.2023

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री अजय राज टांटिया, अभिभाषक  
प्रत्यर्थागण की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :- शुचि शर्मा, सदस्य  
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

## आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यह अनुतोष चाहा गया है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 06.09.2015 को अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को सेवा के दौरान प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्ति के कारण नियम 26ए के तहत दी गई एक वेतन वृद्धि को पूर्व की भांति प्रदान करें और ग्रेच्युटी एवं उपार्जित अवकाश के नकदीकरण का भुगतान नियमानुसार देय अंतिम वेतन रूपये 37,560/- के आधार पर तय कर अंतर की राशि व पेंशन की प्रति माह देय राशि की गणना कर नियमानुसार कम्प्यूटेशन राशि का भुगतान मय ब्याज सहित किया जावे और ग्रेच्युटी की राशि से विधि विरुद्ध कटौती की गई राशि रूपये 76,836/- का भुगतान 18 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज सहित वापिस दिया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :-

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति व्याख्याता के पद पर दिनांक 23.02.1985 को हुई थी और प्रधानाचार्य के पद पर आदेश दिनांक 06.05.2013 के द्वारा पदोन्नति हुई और प्रधानाचार्य के पद से

दिनांक 31.08.2015 को सेवानिवृत्त हुआ। उनका कथन है कि चयनित वेतनमान का लाभ कर्मचारी को विद्यमान पद पर अगली स्टेज पर स्थिरीकरण कर दिया जाता है, परंतु पदोन्नति के समय चयनित वेतनमान प्राप्त कर्मचारी को नियम 26ए का लाभ देते हुए एक वेतन वृद्धि दिया जाना विधि सम्मत है। अपीलार्थी को भी उक्त लाभ दिया गया है, जो विधि सम्मत है। यदि विभाग द्वारा कर्मचारियों को वेतन स्थिरीकरण उपरांत यदि अधिक भुगतान कर दिया जाता है तो कर्मचारी की सेवानिवृत्ति उपरांत उसे वसूला नहीं जा सकता। किसी भी कर्मचारी को ग्रेच्युटी से किसी भी हाल में किसी भी प्रकार की वसूली नहीं की जा सकती। जबकि अपीलार्थी से ग्रेच्युटी के भुगतान से रुपये 76,836/- की वसूली पूर्णतया अवैध है। अपीलार्थी ने अपने विद्वान् अधिवक्ता द्वारा न्याय की मांग का नोटिस दिनांक 20.04.2016 को जारी कर अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 06.09.2015 को अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को सेवा के दौरान प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्ति के कारण नियम 26ए के तहत दी गई एक वेतन वृद्धि को पूर्व की भांति प्रदान करें और ग्रेच्युटी एवं उपार्जित अवकाश के नकदीकरण का भुगतान नियमानुसार देय अंतिम वेतन रुपये 37,560/- के आधार पर तय कर अंतर की राशि व पेंशन की प्रति माह देय राशि की गणना कर नियमानुसार कम्युटेशन राशि का भुगतान मय ब्याज सहित किया जावे और ग्रेच्युटी की राशि से विधि विरुद्ध कटौती की गई राशि रुपये 76,836/- का भुगतान 18 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज सहित वापिस दिया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि प्रत्येक कार्मिक द्वारा अपना वेतन निर्धारण करवाने हेतु विकल्प प्रस्तुत किए जाते हैं, जिसमें यह भी शपथ की जाती है कि कोई भी वेतन निर्धारण गलत/अनियमित स्थिरीकरण होने की स्थिति में ऐसी राशि राज्य सरकार को रिफण्ड के लिए पाबंद रहूंगा। इस प्रकार अनियमित भुगतान की वसूली नियमानुसार है। अपीलार्थी सेवानिवृत्त हो जाने से उसके उपादान में वसूली की गई। चयनित वेतनमान मिलने पर नियम 26ए का लाभ प्राप्त कर लिए जाने के कारण पदोन्नति पर दुबारा नियम 26ए का लाभ देय नहीं है और सहवन से लाभ दुबारा दिया जाता है तो नियमानुसार वसूली योग्य है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति व्याख्याता के पद पर दिनांक 23.02.1985 को हुई थी और प्रधानाचार्य के पद पर आदेश दिनांक 06.05.2013 के द्वारा पदोन्नति हुई और प्रधानाचार्य के पद से दिनांक 31.08.2015 को सेवानिवृत्त हुआ। अपीलार्थी से ग्रेच्युटी के भुगतान से रुपये 76,836/- की वसूली की गई है। जहां तक अपीलार्थी से राशि रुपये 76,836/- की वसूली किए जाने का प्रश्न है, आदेश दिनांक 31.08.2015 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी दिनांक 31.08.2015 को मध्याह्न पश्चात राज्य सेवा से सेवानिवृत्त कर दिया गया और सेवानिवृत्ति पश्चात् अपीलार्थी से उक्त राशि की वसूली की गई है, जो उसके उपादान आदि से वसूली की गई, जो हमारे मत में माननीय न्यायालयों के न्यायिक दृष्टान्तों एवं विधि के विरुद्ध है। ऐसे मामलों में कार्मिकों को पूर्व में भुगतान की गई राशि की वसूली किए जाने के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह 2015 (1) SCT 195** के प्रकरण में कार्मिक को भुगतान की गई राशि के सम्बन्ध में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किए हैं :-

***"12. It is not possible to postulate all situations of hardship, which would govern employees on the issue of recovery, where payments have mistakenly been made by the employer, in excess of their entitlement. Be that as it may, based on the decisions referred to herein above, we may, as a ready reference, summarise the following few situations, wherein recoveries by the employers, would be impermissible in law:***

- (i) Recovery from employees belonging to Class-III and Class-IV service (or Group 'C' and Group 'D' service).***
- (ii) Recovery from retired employees, or employees who are due to retire within one year, of the order of recovery.***
- (iii) Recovery from employees, when the excess payment has been made for a period in excess of five years, before the order of recovery is issued.***
- (iv) Recovery in cases where an employee has wrongfully been required to discharge duties of a higher post, and has been paid accordingly, even though he should have rightfully been required to work against an inferior post.***
- (v) In any other case, where the Court arrives at the conclusion, that recovery if made from the employee.***

***would be iniquitous or harsh or arbitrary to such an extent, as would far outweigh the equitable balance of the employer's right to recover."***

यह कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह 2015 (1) SCT 195 वाले प्रकरण में यह अवधारित किया है कि इस प्रकार मामलों में वसूली नहीं की जा सकती है। अपीलार्थी ने कभी भी कोई misrepresentation या धोखाधड़ी नहीं की है। इस कारण उसको जो भुगतान किया गया है, वह नियमानुसार किया गया है। उसकी वसूली किया जाना अवैधानिक है। अतः अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 06.09.2015 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जाता है और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि यदि अपीलार्थी से उक्त आदेश की पालना में कोई वसूली की गई है तो उसे नियमानुसार एवं न्यायिक दृष्टान्तों को दृष्टिगत रखते हुए वापिस लौटाई जावे। अतः उक्त निर्देशों के साथ अपील अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)  
सदस्य

(शुचि शर्मा)  
सदस्य